राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर,शनिवार, 23 मई 2026

वर्ष 14, अंक 44, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

लखनऊ विश्वविद्यालय में अब एग्जाम कॉपियों के मूल्यांकन में होगी स्टेप मार्किंग, लाखों छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ...03

मिट जाओगे', अमेरिका की धरती से पाकिस्तानी सांसद ने भारत के खिलाफ उगला जहर...04

क्या हर IAS-डॉक्टर को OBC आरक्षण का फायदा नहीं मिलता? सुप्रीम कोर्ट के सवाल से उठा क्रीमी लेयर का मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अगर माता-पिता दोनों ड्डस् अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? जस्टिस बीवी नागरत्ना एवं जस्टिस उजल भुयन ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य उन परिवारों को ऊपर उठाना है, जो अभी भी पिछड़े हैं. अगर कोई परिवार पहले ही शिक्षा, नौकरी, सम्मान और संसाधनों के स्तर पर आगे निकल चुका है, तो उसके बच्चों को उसी तरह आरक्षण देना क्या उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है लेकिन एक बार क्रीमी लेयर को लेकर सवाल फिर ताजा हो गया है. आइए इसी बहाने जानते हैं कि क्रीमी लेयर क्या है? ओबीसी आरक्षण में किसे मिलता है फायदा और किसे नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उठाया सवाल?

क्या है क्रीमी लेयर का मतलब?

भारत में आरक्षण का उद्देश्य केवल सीटें बांटना नहीं है. इसका असली मकसद उन वर्गों को आगे लाना है, जो लंबे समय तक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रहे. ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को इसी सोच के तहत आरक्षण दिया गया. लेकिन ओबीसी के भीतर भी एक ऐसी श्रेणी मानी गई, जो बाकी लोगों की तुलना में काफी आगे निकल चुकी है. क्रीमी लेयर का मतलब है OBC वर्ग के भीतर वह हिस्सा, जो आर्थिक, सामाजिक या प्रशासनिक रूप से मजबूत हो चुका है. ऐसे परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता. आरक्षण का फायदा उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो अभी भी पीछे हैं. यानी हर ओबीसी व्यक्ति अपने आप आरक्षण का हकदार नहीं होता. अगर परिवार की स्थिति बहुत मजबूत है, तो वह क्रीमी लेयर में माना जा सकता है. ऐसे में उसे आरक्षण नहीं मिलेगा.

क्रीमी लेयर की जरूरत क्यों पड़ी?

जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, तब यह डर भी सामने आया कि इसका लाभ बार-बार वही परिवार न उठा लें जो एक बार आगे बढ़ चुके हैं. अगर ऐसा होता, तो ओबीसी के सबसे कमजोर समुदाय पीछे ही रह जाते. इसी कारण क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई गई. इसका सीधा उद्देश्य था कि आरक्षण का फायदा ओबीसी के गरीब, वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले तबकों तक पहुँचे. यानी जो परिवार पहले से मजबूत हो चुके हैं, उन्हें इस सुविधा से बाहर किया जाए.

ओबीसी आरक्षण में किसे मिलता है फायदा?

ओबीसी आरक्षण का लाभ सामान्य रूप से उन लोगों को मिलता है जो ओबीसी सूची में आते हों. नॉन-क्रीमी लेयर में हों. तय नियमों और प्रमाणपत्रों को पूरा करते हों. सरकारी नौकरियों और कई शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है. लेकिन यह लाभ सिर्फ नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी को मिलता है. यही सबसे महत्वपूर्ण बात है. बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रीमी लेयर केवल आय से तय होती है, यह पूरी तरह सही नहीं है.

किसे नहीं मिलता फायदा?

ओबीसी के भीतर वे लोग आरक्षण से बाहर हो सकते हैं, जिनके परिवार की सामाजिक, प्रशासनिक या आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो चुकी हो. आम तौर पर ऐसे मामलों में क्रीमी लेयर लागू होती है. सरकारी नियमों के अनुसार, कुछ स्थितियों में माता-पिता की पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है. केवल आय ही नहीं देखी जाती. उदाहरण के लिए अगर माता या पिता संवैधानिक पद पर रहे हों, माता-पिता सीधे ग्रुप-ए सेवा में रहे हों, पैरेंट्स ग्रुप-बी सेवाओं में हों, अगर परिवार उच्च प्रशासनिक स्तर तक पहुंच चुका हो, ऐसे मामलों में बच्चों को क्रीमी लेयर में माना जा सकता है. यानी ओबीसी होने के बावजूद उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.

क्या केवल आय से तय होती है क्रीमी लेयर?

बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रीमी लेयर केवल आय से तय होती है. यह पूरी तरह सही नहीं है. आय एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन हर मामले में यही अकेला आधार नहीं होता. आम चर्चा में 8 लाख रुपये सालाना की सीमा का जिक्र होता है. लेकिन सरकारी नौकरी वाले परिवारों के मामलों में कई बार माता-पिता की नौकरी की श्रेणी और पद भी देखे जाते हैं. यानी कोई व्यक्ति केवल कम या ज्यादा वेतन के आधार पर ही क्रीमी लेयर में नहीं आता. उसका सामाजिक और प्रशासनिक दर्जा भी मायने रखता है.

8 लाख या उससे ज्यादा सालाना आय है तो क्या?

इस ताजी बहस के बीच ओबीसी के अलावा अन्य वर्गों के लिए भी यह जानना जरूरी है कि सरकारी सेवा के बाहर जो लोग हैं, उनका कैसे तय होगा कि वे गरीब हैं या अमीर? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी कुमार दुबे कहते हैं कि इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने पहले से ही स्पष्ट व्यवस्था कर रखी है. आठ लाख रुपये या उससे ऊपर की सालाना आय वाला कोई भी व्यक्ति न तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभ ले सकता है और न ही किसी और तरीके का सरकारी लाभ. चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या निजी क्षेत्र में काम करने वाला अधिकारी-कर्मचारी. आठ लाख या उससे ज्यादा सालाना आय का मतलब हुआ कि आप की स्थिति ठीक है.

फसल नुकसान का आकलन होने के बावजूद राहत न देना किसानों के आजीविका के अधिकार का उल्लंघनः पटना हाईकोर्ट

● पटना हाईकोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने वाले किसानों को केवल प्रक्रियात्मक कारणों के आधार पर मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता।

● अदालत ने टिप्पणी की कि देश का पेट भरने वाले किसान को संकट के समय अपने हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता।

● चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ फसल क्षति से जुड़े मुआवजे के मामले पर सुनवाई कर रही थी।

ब्यूरो प्रयागराज। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने वाले किसानों को केवल प्रक्रियात्मक कारणों के आधार पर मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि देश का पेट भरने वाले किसान को संकट के समय अपने हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। फसल नुकसान का आकलन होने के बावजूद राहत न देना किसानों के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है।

चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ फसल क्षति से जुड़े मुआवजे के मामले पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बिहार कृषि विभाग के निदेशक, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी और साहेबगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।

दालत को बताया गया कि मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने पहले फसल नुकसान का आकलन कर अंतरिम मुआवजे की रिपोर्ट सौंपी थी लेकिन कृषि विभाग ने यह कहते हुए आगे कार्रवाई नहीं की कि रबी सीजन शुरू हो चुका है।

कृषि विभाग के निदेशक ने अदालत को बताया कि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से संचालित की गई थी। योजना के तहत आवेदन पोर्टल 2 दिसंबर 2025 तक खुला था और तय समय सीमा में आवेदन करने वाले पात्र किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है।अदालत के समक्ष बताया गया कि अब तक कुल 1 लाख 11 हजार 861 किसानों को फसल नुकसान के लिए 33 करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई।

हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि कृषि विभाग ने अब तीन सदस्यीय समिति गठित की, जो प्रभावित पंचायतों में जाकर उन किसानों की पहचान करेगी जिनके दावे अब तक लंबित या अनदेखे रह गए। समिति को मौके पर जांच कर फसल नुकसान का आकलन करने और 15 दिनों के भीतर समेकित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

अदालत ने कहा कि यदि जांच में ऐसे किसान पात्र पाए जाते हैं, जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है, तो उन्हें शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिया गया कि व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर प्रभावित किसानों को समिति के समक्ष उपस्थित होने की जानकारी दी जाए।

पटना हाईकोर्ट ने कहा, 'यह कहना आवश्यक है कि पूरे देश का पेट भरने वाले किसान को तब अपने हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता, जब प्राकृतिक आपदा उसकी फसल को तबाह कर दे। 'अदालत ने आगे कहा कि फसल नुकसान का आकलन होने के बावजूद राहत न देना किसानों के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी वास्तविक और पात्र किसान केवल प्रक्रियात्मक अड़चनों के कारण मुआवजे से वंचित नहीं रहना चाहिए।

संक्षिप्त ख़बरें

डीएम ने निर्माणाधीन उप निबन्धक कार्यालय बांसी का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा निर्माणाधीन उपनिबन्धक कार्यालय, बांसी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा निर्माणाधीन भवन को देखा गया। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि निर्माण कार्य निर्धारित समय में एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराये। इसके साथ ही थर्ड पार्टी सत्यापन कराने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उपमहानिरीक्षक निबन्धक बस्ती मण्डल, बस्ती शशि भानु मिश्र, सहायक महानिरीक्षक निबन्धक ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, उप निबन्धक बांसी राकेश राम व अन्य संबधित उपस्थित रहे।

आगरा में पारा 46 डिग्री पार, डीएम ने दिए भीषण गर्मी में जिले के सभी बोर्ड के स्कूलों में छुट्टी करने के आदेश

आगरा। जिले में बढ़ते तापमान और मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी हीट वेव एवं अत्यधिक गर्मी की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। डीएम मनीष बंसल के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने जिले के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त, वित्तविहीन, परिषदीय व सभी बोर्ड (सीबीएसई, सीआईएससीई, यूपी बोर्ड, मदरसा बोर्ड आदि) से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा एक से 12 तक के लिए एक सप्ताह का अवकाश घोषित किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्र शेख और जिला बेसिक शिक्षाधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड के आदेशानुसार 21 मई से आगामी एक सप्ताह तक कक्षाओं का संचालन पूर्ण रूप से स्थगित रहेगा। डीएम ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जारी आदेश में सभी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी स्कूल में आदेश के बावजूद कक्षाएं संचालित पाई जाती हैं तो संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यालय प्रशासन की होगी।

निर्माण कार्यों में लापरवाही पर डीएम सख्त, एई का वेतन रोका

» कई परियोजनाओं का किया औचक निरीक्षण

बस्ती। बस्ती जिलाधिकारी ने गुरुवार को विकास खण्ड परसरामपुर क्षेत्र के विभिन्न निर्माणाधीन और संचालित परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सबसे पहले विकास खण्ड परसरामपुर पहुंचकर ब्लॉक परिसर, शिकायत पटल, एकाउंट कक्ष, आवासीय परिसर और पत्रावलियों का निरीक्षण किया। यहां व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने धरमपुर स्थित निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हाइड्रोलिक लैब, वर्कशॉप, क्लासरूम, सड़क निर्माण, शौचालय, किचन और आवासीय भवनों का जायजा लिया गया। मौके पर केवल 10 श्रमिक कार्य करते पाए गए, जिससे निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी मिली। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एई अरविन्द कुशवाहा का वेतन बाधित करने और स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। धरमपुर के निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम में जिलाधिकारी ने परियोजना की ड्राइंग और कार्य प्रगति का अवलोकन किया। कार्यदायी संस्था ने जानकारी दी कि परियोजना को मई 2027 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्टेडियम निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल अवगत कराया जाए ताकि समय से समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ग्राम पंचायत नारायणपुर स्थित वृहद गोसंरक्षण केन्द्र भी पहुंचीं। यहां उन्होंने पशुचिकित्साधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव से गौशाला के मानकों, पानी, भूसा गोदाम, विद्युत व्यवस्था और हरे चारे की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। स्थानीय लोगों ने बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के स्थायी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने गौशालाओं की बाउंड्रीवाल का कार्य शीघ्र पूरा कर हैंडओवर करने तथा उपयुक्त भूमि चिन्हित कर नैपियर घास की बुआई की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। हरैया स्थित पौधशाला में जिलाधिकारी ने जामुन, आम, नींबू, सागवान, सेमर और अन्य छायादार व फलदार पौधों का निरीक्षण किया। उन्होंने डीएफओ डॉ. शिरीन सिद्दीकी को निर्देशित किया कि गौशालाओं की सूची उपलब्ध कराकर वहां आवश्यकतानुसार पौधरोपण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। निरीक्षण के दौरान डीएफओ डॉ. शिरीन सिद्दीकी, पशुचिकित्साधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव, खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार सिंह, एई अरविन्द कुशवाहा, एक्सईएन आरईडी अंकुर वर्मा, सुपरवाइजर प्रदीप सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

साइबर हेल्प डेस्क कोइरौना ने लौटाए 13 हजार रुपये

भदोही। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में साइबर हेल्प डेस्क थाना कोइरौना ने साइबर फ्रॉड के शिकार युवक के खाते से कटे 13 हजार रुपये वापस कराए। ग्राम जुड़उपुर निवासी विशाल कुमार सरोज ने साइबर ठगी की शिकायत थाना कोइरौना में की थी। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर हेल्प डेस्क ने संबंधित माध्यमों से समन्वय स्थापित कर पूरी धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करा दी। खाते में रकम वापस मिलने पर पीड़ित ने भदोही पुलिस और साइबर हेल्प डेस्क का आभार जताया। पुलिस ने लोगों से साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहने और किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करने की अपील की।

कप्तानगंज में अभी भी बचे रह गए भ्रष्टाचार के गुरुघंटाल, चेले को ले गयी एंटीकरप्सन

» एडीओ पंचायत व सीडीपीओ कार्यालय की भूमिका सवालों के घेरे
मेंसफाई कर्मचारी की गिरतारी, बीडीओ की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में
» खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी जल्द धमकेगी एंटीकरप्सन टीमखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रभात श्रीवास्तव भी नगर बाजार में बैठकर करते हैं कप्तानगंज व बहादुरपुर लाकों की वसूली

बस्ती। एक ओर सरकार जहाँ जीरो टालरेंस का ढिंढोरा पीट रही है तो वहीं कप्तानगंज ब्लाक भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है जिसकी पुष्टि एंटीकरप्सन टीम ने 25000 रुपया घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तारी करके किया। कप्तानगंज विकास खंड मुख्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल की खबरें अक्सर मीडिया में सुर्खियाँ बन रही हैं परन्तु जिम्मेदार मनमानी से बाज नहीं आ रहे और भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी है । मामला चाहे बीडीओ के परसेंटेज वाली वसूली से जुड़ा हो या फिर चाहे एडीओ पंचायत के सफाई कर्मचारियों के समायोजन/तैनाती में धनउगाही से हो जुड़ा हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। विकास खण्ड परिसर में स्थापित सभी कार्यालय यथा वनक्षेत्राधिकारी व बाल विकास परियोजना कार्यालय सभी में धनउगाही की गति समान ही है। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी जिसके मुखिया प्रभात कुमार श्रीवास्तव हैं वहाँ तो और ही भ्रष्टाचार है क्योंकि वहाँ के मुखिया प्रभात के पास कप्तानगंज व बहादुरपुर दो ब्लाकों का चार्ज है और नगर बाजार में बैठकर दोनों ब्लाकों की वसूली एक ही जगह से की जाती है । सूत्रों की माने तो कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कप्तानगंज का जल्द ही एंटीकरप्सन टीम बृहद आपरेशन करने वाली है क्योंकि तमाम संदिग्ध गतिविधियाँ खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रभात द्वारा संचालित हैं जो कार्यवाही का आधार बनेंगी। आइए एक नजर सफाई कर्मचारी की गिरफ्तारी पर डालें जो कि आंगनबाडी में नियुक्ति से संबंधित है मतलब साफ है कि आंगनवाड़ी की भर्ती भी भ्रष्टाचार का शिकार है जिम्मेदार भले ही अपने आप को दूध का धुला बताएं क्योंकि साक्ष्य सबके सामने है। देखना यह है कि इस कार्यवाही में बीडीओ अपने कार्यप्रणाली में सुधार लायेंगे या अगला विकेट गिरने का इंतजार करेंगे।

सीएमओ कार्यालय का वरिष्ठ सहायक पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कार्रवाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर। बलरामपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन टीम) देवीपाटन मण्डल गोण्डा की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता शिवचरनलाल निवासी धुसाह थाना कोतवाली देहात, जो वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय बलरामपुर में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत हैं, ने एंटी करप्शन संगठन से शिकायत की थी। आरोप था कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रीइम्बर्समेंट) की जांच कर प्रतिहस्ताक्षरित कराने के एवज में सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक मोहनलाल जायसवाल द्वारा 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।शिकायत को गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोण्डा इकाई के प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में ट्रैप टीम गठित की गई। टीम ने गुरुवार दोपहर करीब 12:40 बजे जाल बिछाकर आरोपी को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट के सामने सड़क पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मोहनलाल जायसवाल पुत्र स्वर्गीय रामप्यारे जायसवाल मूल रूप से ग्राम फुलवरिया, थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर का निवासी बताया गया है। वह वर्तमान में बलरामपुर सीएमओ कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है। एंटी करप्शन टीम ने आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली देहात में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या संविदाकर्मी रिश्वत की मांग करता है तो तत्काल शिकायत करें।

मय माता स्थान के बगल पोखरा का कई बार हो चुका है भुगतान उसी पोखरा का पुनः जारी है मस्टर रोल

● रोजगार सेवक किरन की आईडी से लग रही मनरेगा मजदूरों की बेधड़क लग रही फर्जी हाजिरीसमय माता स्थान के बगल पोखरा खुदाई व सफाई कार्य के नाम पहले भी हो चुका है कई बार भुगतान

● समय माता स्थान के बगल पोखरा खुदाई व सफाई कार्य के नाम पर बार - बार मस्टर रोल जारी होने पर सचिव, टीए व मनरेगा एपीओ की भूमिका संदिग्ध

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्तीजिले के विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोयलसा में मनरेगा एक्ट की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वर्तमान समय में दो पोखरा (तालाब) खुदाई व सफाई कार्य के नाम पर फर्जी मस्टर रोल जारी है और दोनों फर्जी मस्टर रोल पर रोजगार सेवक किरन बेधड़क मनरेगा मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाने में मस्त हैं और मनरेगा मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर ग्राम प्रधान सावित्री देवी से वाह-वाही लूट रही है ।

सूत्रों की माने तो समय माता स्थान के बगल पोखरा खुदाई व सफाई का कार्य लगभग 06 महीने से चल रहा है और कई बार उक्त प्रोजक्ट के नाम पर भुगतान भी हो चुका है लेकिन कई बार समय माता स्थान के बगल पोखरा खुदाई व सफाई कार्य के नाम पर भुगतान होने के बाद भी बार - बार फर्जी मस्टर रोल जारी होने पर रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, सचिव व तकनीकी सहायक एवं मनरेगा एपीओ की भूमिका अहम है।

मीडिया टीम ने पूर्व में ग्राम पंचायत कोयलसा में चल रहे मनरेगा कार्यों का धरातलीय पड़ताल किया था तब ग्राम प्रधान सावित्री देवी , रोजगार सेवक किरन और सचिव शिव शंकर यादव व तकनीकी सहायक एवं मनरेगा एपीओ के लूट खसोट की पोल खुली थी लेकिन खण्ड विकास अधिकारी सल्टौवा गोपालपुर अनिल कुमार यादव ने ग्राम पंचायत कोइलसा में चल रहे फर्जीवाड़ा मामले का संज्ञान नही लिया था जिसके कारण फर्जी भुगतान कराने में ग्राम प्रधान सावित्री देवी व सचिव शिव शंकर यादव ने बाजी मारी थी। फर्जी भुगतान कराने में सफल होने पर पुनः फर्जी मस्टर रोल के सहारे ग्राम प्रधान सावित्री देवी व सचिव शिव शंकर यादव सरकारी खजाने को लूटने की तैयारी में जुटे हुए हैं।

ग्राम पंचायत कोयलसा में बड़े पैमाने पर चल रहे मनरेगा फर्जीवाड़ा को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है और ग्राम प्रधान सावित्री देवी व सचिव शिव शंकर यादव के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी बना रहे हैं। ग्रामीणों ने बातचीत में बताया कि पंचायत चुनाव नजदीक है जिसके कारण ग्राम प्रधान व सचिव ने सरकारी खजाने को लूटने के उद्देश्य से धड़ल्ले से मनरेगा फर्जीवाड़ा करने में मस्त हैं। अब देखना यह है कि बीडीओ अनिल कुमार यादव ग्राम पंचायत कोयलसा के भ्रष्टाचार को रोक पाते हैं या नही। अथवा लेनदेन करके मामले को रफा-दफा कर देंगे।

प्रतिभाशालियों के हौसले तोड़ता रोज-रोज का पेपर लीक

भारत में एक बार फिर प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक एकदम आम सा हो गया है। जितनी सहजता से खामियों को छुपाते हुए परीक्षा रद्द कर दी जाती है, उसके एवज में लाखों बच्चों के मनोमस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा, समझने की कोशिश भी नहीं का जाती। यह अफसरशाही नहीं तो क्या है? अबकी बार नीट यूजी 2026 पेपर लीक ने फिर तमाम व्यवस्थाओं और परीक्षा तंत्र पर करारा तमाचा जड़ा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ और जो तौर-तरीके देखने में आ रहे हैं उससे लगता है कि न ही आखिरी बार होगा। सबसे पहले बात 3 मई 2026 को भारत भर में हुई उस परीक्षा की जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र देश-समाज के लिए कुछ करने की लालसा लिए नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए। उन्हें उम्मीद थी कि उनका सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सपने चूर-चूर हो गए। महज एक बयान जारी कर नौ दिन बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल कोर्सों में दाखिले खातिर होने वाली नीट-यूजी की परीक्षा रद्द कर दी। वजह बताई गई कि एजेंसी को 7 मई को एक व्हिसलब्लोअर ने जानकारी दी कि एक 'गेस पेपर' का पीडीएफ व्हाट्सऐप पर सर्कुलेट किया गया था, जिसमें वास्तविक नीट परीक्षा जैसे ही प्रश्न थे। एनटीए के महानिदेशक ने कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह का उल्लंघन हमारी ज़ीरो-टॉलरेंस नीति के ख़िलाफ़ है और इससे उन 22 लाख छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है जिन्होंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी। बयान के लब्बोलुआब में नपे-तुले शब्दों से अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूर पापड़ बेले गए। लेकिन अब उन लाखों बच्चों का क्या होगा जिन्हें लीक पेपर से कोई वास्ता नहीं था, पेपर अच्छा गया था लेकिन, चयन तय था, लेकिन सपने एक झटके में टूट गए! क्या एनटीए को भान होगा कि बच्चों के कोमल मनोमस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा? जब परीक्षा के पहले ही पीडीएफ बिके, सोशल मीडिया पर वायरल संदेश और सौदेबाजी की बातें हो रहीं थीं तब सारी एजेंसियों के कान में तेल पड़ा था? परीक्षा कोई भी हो, उसकी पवित्रता और निष्पक्षता का ध्यान रखने की गुरुतर जिम्मेदारी उन्हें संचालित करने वालों की होती है।

भारत में कुछ पेपर लीक बहुत ही सुर्खियों, विवादों और चर्चाओं में रहे हैं। ऐसे कुछ मामले आज भी लोगों को भुलाए नहीं भूलते। इनमें मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) का 2013 का मामला काफी चर्चित है। इसमें नकली परीक्षार्थी (सॉल्वर) दूसरों की जगह परीक्षा में सम्मिलित हुए। लंबी रकम देकर इस तरह नौकरियां में जाने का रास्ता भी बना था लेकिन पकड़े गए। मामले में कई आरोपियों सहित जाँच एजेंसियों के लोगों की संदिग्ध मौतें भी हुईं। तब पूरा मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए भी गले की हड्डी बना। आरोप-प्रत्यारोपों की झड़ी लगी लेकिन सभी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। एक अन्य मामला कर्मचारी चयन आयोग का सामने आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रणाली को दूषित बता दिया। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) 2017 परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो गया। सीबीआई जांच में पता चला कि कुछ परीक्षा केंद्रों के सुपरवाइजर्स ने अभ्यर्थियों को रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए बाहरी मदद दिलवाई थी। 2022 में रेलवे भर्ती विवाद में सवा करोड़ युवाओं का सड़कों पर उबाल दिखा जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट पर आपत्ति उठाई। 2024 में यूजीसी नेट की परीक्षा दूसरे ही दिन रद्द कर दी गई जिसमें 9 लाख प्रतिभागियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया जो पीएचडी करने और प्रोफेसर बनने का सपना संजोए हुए थे। बहुचर्चित नीट-2024 में 67 छात्रों का 720 अंक ही अर्जित करना सुर्खियों में रहा। इसमें झारखण्ड के एक प्रिन्सपल और वाइस प्रिन्सपल ने पर्चा चुराकर लाखों में बेचा था। जिससे सभी के समान अंक आए और मामले ने तूल पकड़ा।

आखिर इतनी जिम्मेदार परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना न केवल एनटीए बल्कि उन सारी छोटी-बड़ी उन एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल है जिनके कंधों पर परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता का बोझ है। सवाल यह भी है कि अब तक देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक हुआ? महज प्रिलिम परीक्षा के दौरान 1992 में इलाहाबाद केंद्र पर पेपर लीक होने की शिकायत आई थी जिस पर संसद में बहस हुई थी। सीबीआई जांच में भी यह सिर्फ एक इनविजिलेटर द्वारा पेपर कॉपी करने का मामला निकला न कि लीक का।

आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। इसी बार अब तक कई परीक्षार्थियों ने आत्मघाती कदम उठा लिया है। यह बहुत दुखद है। इसे कौन समझेगा? किस पर बच्चों के कोमल मन को झकझोरने और उन्हें ना समझी में बुरे कदम उठाने का आरोप लगेगा? बहुत ही दुखद है मेहनत के बाद इस तरह की घटनाएँ जहाँ रिवाज बन गई हैं वहीं कई प्रतिभाशाली अपने जीवन को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। पिछले 12-13 वर्षों के छोटे-बड़े मामले देखें तो लगभग सैकड़ा पार हो चुका है। तकरीबन दो करोड़ छात्रों के भविष्य पर हर वर्ष असर पड़ता है। कई उम्र की सीमा लांघ चुके होते हैं तो कई का मनोबल टूटता और बेहतर करने के बजाए अवसाद का शिकार हो जाते हैं जीवन से हाथ धो लेते हैं। उधर एजेंसियां ईमानदारी के नाम पर खुद को कटघरे में पाकर पेपर ही कैंसल कर, दोबारा कराने का आदेश देकर बरी और ईमानदार हो जाती हैं। इधर मामले बनते हैं और अपराधी कटघरे में भी पहुंचते हैं लेकिन अनेकों बार देखने में आया कि निश्चित समय-सीमा में चार्ज शीट दाखिला में देरी से वो भी बाहर आकर दोबारा अपने पुराने कार्यों मे संलग्न हो जाते हैं।

पेपर लीक को लेकर सरकार को सख्त होना पड़ेगा। कहने को तो कई आरोपी अब तक गिरफ्त मे आ चुके हैं। लेकिन इसका हल ढूंढ़ना ही होगा, संसद में बहस करनी होगी, कठोरतम व्यवस्था व प्रभावी कानून बनाने होंगे ताकि लोग पेपर लीक करने या कराने के नाम से ही थर्राने लगे और इस बारे में सोचना ही बंद कर दें। इसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) को रोल मॉडल मान इससे सीख लेनी चाहिए। परीक्षाओं की पवित्रता की गारन्टी हुक्मरानों और अफसरों को लेनी ही होगी ताकि प्रतिभाशालियों का हौसला बार-बार न टूटे और विचलित भी न हों।

ऋतुपर्ण दवे

युवाओं की तीखी प्रतिक्रिया, हम कॉकरोच हैं, लेकिन दीमक नहीं

संपादक/लेखकः राजीव शुक्ला

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के एक मौखिक टिप्पणी ने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया है। बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने वाले बयान के बाद सोशल मीडिया पर युवा वर्ग ने तीखा विरोध जताते हुए कहा- हम कॉकरोच हैं, लेकिन दीमक नहीं!

घटना पंद्रह मई की है, जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम संबंधी एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे। अदालत में उन्होंने कहा था, कुछ युवा कॉकरोच जैसे होते हैं, जिन्हें न रोजगार मिलता है और न पेशे में जगह। वे मीडिया, सोशल मीडिया, सूचना अधिकार एक्टिविस्ट बनकर व्यवस्था पर हमला करते हैं। उन्होंने फर्जी उपाधि वाले वकीलों और परजीवियों को भी निशाने पर लिया।

बयान वायरल होते ही युवा, विपक्षी नेता और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता भड़क उठे। कई युवाओं ने तर्क दिया कि बेरोजगारी की समस्या व्यवस्था की है, न कि युवाओं की। एक व्यापक प्रतिक्रिया में लोग लिख रहे हैं- हम कॉकरोच हैं जो खुले में लड़ते हैं, लेकिन दीमक वे हैं जो अंदर से देश को खोखला कर रहे हैं। कॉकरोच को संघर्ष और जीवट के प्रतीक के रूप में पेश करते हुए युवा कह रहे हैं कि वे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं, जबकि दीमक चुपके से संरचना को नष्ट करते हैं।

मुख्य न्यायाधीश की सफाईः विवाद बढ़ने पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोलह मई को स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया। उनका इरादा देश के युवाओं की आलोचना नहीं था, बल्कि फर्जी उपाधियों के जरिए पेशों में घुसपैठ करने वालों पर था। मुख्य न्यायाधीश ने युवाओं को देश के स्तंभ बताया

और कहा कि वे उनसे प्रेरित होते हैं।

विवाद का पृष्ठभूमिः भारत में युवा बेरोजगारी की दर पंद्रह से सत्रह प्रतिशत के आसपास बताई जाती है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटालों, नौकरियों की कमी और महंगाई जैसे मुद्दों पर युवा पहले से असंतुष्ट हैं। मुख्य न्यायाधीश के बयान को कई लोग युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश मान रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी इस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर हमकॉकरोचहैं और दीमकबनामकॉकरोच जैसे हैशटैग चर्चा में हैं। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, कॉकरोच तो दिख जाता है, लेकिन दीमक अंदर से खाती रहती है- चाहे वह भ्रष्टाचार हो, संस्थागत गिरावट हो या युवाओं की उपेक्षा।

विशेषज्ञों की रायः सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् मानते हैं कि बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। इसे कॉकरोच कहकर खारिज करने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि युवाओं में गुस्सा बढ़ेगा। साथ ही फर्जी उपाधि और व्यवस्था में घुसपैठ को रोकने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। यह विवाद एक बार फिर बेरोजगारी, मेरिट और संस्थागत विश्वास पर बहस छेड़ गया है। युवा साफ कह रहे हैं- हम टिके रहने वाले कॉकरोच हैं, लेकिन देश को खोखला करने वाले दीमक नहीं। अब देखना यह है कि इस पलटवार से व्यवस्था कितना सबक लेती है।

आत्मविश्वास और धर्मशक्ति से ही बनता है समाज और राष्ट्र महान

मनुष्य के जीवन में सफलता का आधार केवल साधन और सुविधाएं नहीं होतीं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने अपने आत्मविश्वास, परिश्रम और सही कार्यपद्धति को अपनाया, उन्होंने अभावों के बीच भी महान उपलब्धियां प्राप्त कीं। दूसरी ओर अनेक ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके पास पर्याप्त धन, संसाधन और अवसर होने के बावजूद वे जीवन में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सके। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में प्रगति का मूल आधार बाहरी साधन नहीं बल्कि व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, सकारात्मक सोच और कर्मशीलता होती है।

आज समाज में एक बड़ी समस्या यह दिखाई देती है कि अधिकांश लोग अपनी असफलताओं का कारण साधनों की कमी को मानते हैं। वे यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि यदि उनके पास अधिक धन, अच्छी व्यवस्था या विशेष अवसर होते तो वे भी जीवन में आगे बढ़ सकते थे। यह सोच वास्तव में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। अभावों को बहाना बनाकर बैठ जाना व्यक्ति के आत्मबल को समाप्त कर देता है। आलस्य और प्रमाद हमेशा किसी न किसी बहाने की तलाश में रहते हैं और साधनों का अभाव सबसे आसान बहाना बन जाता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग ही नहीं कर पाता और धीरे-धीरे उसका व्यक्तित्व कुंठित होने लगता है।

यदि हम संसार के महान व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करें तो पाएंगे कि अधिकांश महान कार्य अभावों के बीच ही संपन्न हुए हैं। अनेक वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, समाज सुधारकों और राष्ट्रनिर्माताओं ने कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए इतिहास रचा। उनके पास आधुनिक साधन नहीं थे, लेकिन उनके भीतर आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा थी। यही कारण है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर दुनिया को नई दिशा दी। अभावों ने उनके भीतर संघर्ष की ज्वाला पैदा की और वही संघर्ष उनकी सफलता का आधार बना।

मनुष्य के पास सबसे बड़ा साधन उसका मस्तिष्क और उसका शरीर है। यदि व्यक्ति का विचार स्वस्थ है और उसका संकल्प दृढ़ है तो वह सीमित संसाधनों में भी असाधारण कार्य कर सकता है। करोड़ों रुपये भी वह सफलता नहीं दिला सकते जो एक जागृत मस्तिष्क और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति सही विधि से कार्य करता है, धैर्य और लगन के साथ आगे बढ़ता है, तब साधन स्वयं उसके मार्ग में आने लगते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। वर्तमान समय में भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या विचारों की विपन्नता भी है। लोग स्वयं पर विश्वास करने के बजाय परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होतीं। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच संघर्ष करना सीख लेता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। राष्ट्र का विकास भी तभी संभव है जब उसके नागरिक आत्मविश्वासी, परिश्रमी और सकारात्मक विचारों वाले हों। केवल सरकारों या व्यवस्थाओं से समाज का उत्थान नहीं हो सकता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसी प्रकार समाज में बढ़ती अनैतिकता और चारित्रिक पतन के लिए भी केवल आधुनिक साधनों या संचार माध्यमों को दोष देना उचित नहीं है। यह सत्य है कि आज के समय में अनेक माध्यमों के द्वारा गलत प्रवृत्तियों का प्रसार होता है, लेकिन समाज का पतन केवल इन कारणों से नहीं होता। वास्तविक समस्या यह है कि समाज में धर्म और नैतिकता की शक्ति कमजोर होती जा रही है। धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांड का नाम नहीं है। धर्म वह शक्ति है जो मनुष्य को सदाचार, संयम, करुणा और मानवता का मार्ग दिखाती है।

जब समाज के सज्जन और धार्मिक लोग निष्क्रिय हो जाते हैं तब दुर्जनता स्वतः बढ़ने लगती है। अधर्म और पापाचार अपने आप में बहुत कमजोर तत्व होते हैं, लेकिन जब उनका विरोध करने वाले मौन हो जाते हैं तब वे समाज पर हावी होने लगते हैं। आज देश में लाखों साधु-संत और करोड़ों धार्मिक लोग हैं, किंतु समाज सुधार और धर्म विस्तार के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करने वालों की संख्या बहुत कम है। केवल मंदिरों में पूजा करना या परंपरागत कर्मकांड निभा लेना ही धर्म नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो समाज में नैतिकता और मानवता की स्थापना करे।

धर्म का वास्तविक स्वरूप समाज के पीड़ित, भटके और दुर्व्यसनग्रस्त लोगों को सही मार्ग दिखाने में है। यदि कोई व्यक्ति नशे, अपराध या अनैतिक जीवन में फंस गया है तो उसे प्रेम, प्रेरणा और सद्विचारों के माध्यम से सुधारना ही धर्म का कार्य है। धर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं बल्कि समाज का कल्याण भी है। जब धार्मिक लोग समाज के बीच जाकर सेवा और जागरण का कार्य करेंगे तभी अधर्म की शक्तियों को रोका जा सकेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज का प्रत्येक सज्जन व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे। यदि अच्छे लोग केवल अपने निजी जीवन तक सीमित रहेंगे और समाज की समस्याओं से दूर रहेंगे तो बुराइयों का बढ़ना स्वाभाविक है। अच्छाई को केवल विचारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे कर्म के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जब सज्जन सक्रिय होंगे तब समाज में नैतिकता, सदाचार और अनुशासन का वातावरण बनेगा।

युवा पीढ़ी को विशेष रूप से यह समझने की आवश्यकता है कि सफलता का मार्ग बाहरी

सुविधाओं से नहीं बल्कि आत्मबल और निरंतर प्रयास से बनता है। उन्हें अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करना होगा। साथ ही समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को भी समझना होगा। केवल व्यक्तिगत सफलता ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि समाज के उत्थान में भी योगदान देना चाहिए। भारत की संस्कृति हमेशा से त्याग, परिश्रम और धर्मनिष्ठा की संस्कृति रही है। इसी संस्कृति ने इस देश को महान बनाया। आज आवश्यकता है कि हम फिर से उन्हीं मूल्यों को अपनाएं। यदि व्यक्ति आत्मविश्वास, परिश्रम और सदाचार को अपने जीवन का आधार बना ले तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन सफल होगा बल्कि समाज और राष्ट्र भी शक्तिशाली बनेंगे।

अंततः यही कहा जा सकता है कि साधन और सुविधाएं जीवन में सहायक अवश्य हैं, लेकिन वे सफलता का मूल आधार नहीं हैं। सच्ची शक्ति मनुष्य के आत्मविश्वास, उसके विचारों और उसके कर्म में होती है। इसी प्रकार समाज की रक्षा केवल कानूनों और व्यवस्थाओं से नहीं हो सकती। इसके लिए सज्जनों और धार्मिक लोगों को सक्रिय होकर समाज में नैतिक जागरण फैलाना होगा। जब व्यक्ति आत्मबल से प्रेरित होकर समाजहित में कार्य करेगा तभी एक स्वस्थ, सशक्त और आदर्श राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। **कांतिलाल मांडोत**

अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस हर घूट में बसी दुनिया की धड़कन

21 मई को दुनिया अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में इसे आधिकारिक मान्यता दी, ताकि चाय उत्पादन से जुड़े लाखों किसानों, श्रमिकों और छोटे उत्पादकों के योगदान को सम्मान मिल सके। सुबह की पहली किरण के साथ जो कप हमारे हाथ में होता है, उसके पीछे असम के बागानों में पत्ती तोड़ती महिलाओं से लेकर दार्जिलिंग की धुंध में लिपटी फैक्ट्रियों और केन्या-श्रीलंका तक फैले खेतों की कहानियां छुपी हैं, जो दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी को जगाते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यहां चाय सिर्फ पेय नहीं, इमोशन है। कुल्हड़ वाली चाय से कश्मीरी कहवे तक, नुक्कड़ की टपरी से 5-स्टार होटल की हाई-टी तक, दोस्ती की शुरुआत से रिश्तों के टूटने तक, हर जगह चाय गवाह बनती है। 'चाय पियोगे?' भारत की सबसे कॉमन लव लैंग्वेज बन चुका है। एक कप चाय का अर्थशास्त्र बेहद गहरा है। दुनियाभर में 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं, जिनमें 60% से ज्यादा महिलाएं हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के लाखों परिवारों की रीढ़ चाय ही है। दुनिया की 70% चाय छोटे किसान उगाते हैं, बड़ी कंपनियां नहीं। मगर जलवायु परिवर्तन, घटते दाम और बिचौलियों की वजह से चाय बागान के मजदूर आज भी 250-300 की दिहाड़ी पर काम करते हैं। इसलिए चाय दिवस का मकसद सिर्फ जश्न नहीं, इन मुद्दों पर आवाज उठाना भी है। सेहत के लिहाज से भी चाय कमाल है। ग्रीन और ब्लैक टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर से लड़ते हैं। रोज 3 कप चाय हार्ट अटैक का खतरा 20% तक कम कर सकती है। इसमें मौजूद L-theanine फोकस बढ़ाता है और स्ट्रेस घटाता है, वहीं बिना दूध-चीनी की चाय ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करती है। इस दिन को मनाने के लिए हम बड़े ब्रांड की जगह सीधे बागानों या छोटे उत्पादकों से चाय खरीद सकते हैं। व्हाइट टी, ऊलोंग, पर्पल टी जैसी नई वैरायटी ट्राई कर सकते हैं। रोज शाम को थकान उतारने वाले चाय वाले भैया को थैंक्यू बोल सकते हैं और प्लास्टिक छोड़कर कुल्हड़ या मिट्टी के कप अपना सकते हैं। चाय का भविष्य चुनौतियों से भरा है। जलवायु परिवर्तन से क्वालिटी और पैदावार दोनों खतरे में हैं। तापमान बढ़ने पर असम की 40% चाय की जमीन बेकार हो सकती है। इसलिए अब सस्टेनेबल टी, ऑर्गेनिक खेती, फेयर ट्रेड और पानी बचाने वाली तकनीक ही इसे बचा पाएगी। टैगोर ने ठीक कहा था, 'चाय है तो उम्मीद है।' 21 मई को जब अगला कप उठाएं, तो उन हाथों को जरूर याद करिएगा जिन्होंने वो पत्ती तोड़ी। चाय दिवस सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों का सम्मान है जिनकी मेहनत हमारी सुबह को 'गुड मॉर्निंग' बनाती है।

डॉ. विवेकानंद उपाध्याय

दैनिक राशिफल

मेष राशि कल का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में रुका धन वापस मिलने के संकेत हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। **शुभ रंगः** लाल **शुभ अंकः** 9

वृषभ राशि धैर्य और समझदारी से काम लेने का दिन है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है। **शुभ रंगः** सफेद **शुभ अंकः** 6

मिथुन राशि कल नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। **शुभ रंगः** हरा **शुभ अंकः** 5

कर्क राशि भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन खर्च बढ़ सकता है लेकिन जरूरी कार्य पूरे होंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। **शुभ रंगः** सिल्वर **शुभ अंकः** 2

सिंह राशि कल आपका प्रभाव बढ़ेगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। करियर में सफलता के संकेत हैं। व्यापार में लाभ हो सकता है। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा। **शुभ रंगः** सुनहरा **शुभ अंकः** 1

कन्या राशि कामकाज में व्यस्तता अधिक रहेगी। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। **शुभ रंगः** हरा **शुभ अंकः** 7

तुला राशि कल भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। **शुभ रंगः** गुलाबी **शुभ अंकः** 6

वृश्चिक राशि गुस्से पर नियंत्रण रखें। किसी करीबी से विवाद हो सकता है। व्यापार में सोच-समझकर निवेश करें। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। **शुभ रंगः** मैरून **शुभ अंकः** 8

धनु राशि कल का दिन उत्साह से भरा रहेगा। करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। यात्रा लाभदायक हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। **शुभ रंगः** पीला **शुभ अंकः** 3

मकर राशि धन लाभ के अच्छे योग हैं। नौकरी में पदोन्नति की चर्चा हो सकती है। पुराने विवाद खत्म होने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। **शुभ रंगः** नीला **शुभ अंकः** 10

कुंभ राशि रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में लाभ मिलेगा। नए लोगों से संपर्क भविष्य में फायदा देगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। **शुभ रंगः** आसमानी **शुभ अंकः** 4

मीन राशि कल मानसिक शांति बनी रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा। व्यापार में लाभ और नौकरी में सराहना मिल सकती है। धार्मिक यात्रा के योग हैं। **शुभ रंगः** नारंगी **शुभ अंकः** 7

मोदी-मेलोनी की मेलोडी डिप्लोमेसी-मुस्कान बनी मैसेज, मिठास बनी मैप

[मोदी-मेलोनी के बीच 'मेलोडी' मूवः बदलते शक्ति संतुलन की झलक]

[मेलोनी को टॉफी, विपक्ष को तमाचा- मोदी ने रोम में नया इतिहास रचा]

रोम की ऐतिहासिक प्राचीरों के साए में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी का पैकेट भेंट किया, तो दुनिया ने सिर्फ एक मीठा पल नहीं, बल्कि वैश्विक विश्व व्यवस्था में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव का स्पष्ट संकेत देखा। यह 'मेलोडी' डिप्लोमेसी महज वायरल सेल्फी या कोलोसियम की सैर नहीं थी। यह दो मजबूत राष्ट्रवादियों के बीच उस रणनीतिक गठबंधन की शुरुआत थी, जो यूरोप के मध्य में भारत को नया द्वार खोल रहा है। जबकि विपक्ष 'टॉफी डिप्लोमेसी' पर तंज कस रहा है, हकीकत यह है कि मोदी की इस यात्रा ने भारत-इटली संबंधों को 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' स्तर पर ऊंचा उठा दिया है। पुरानी कांग्रेस संस्कृति की 'चाय पी लो' वाली आलोचना अब पुरानी पड़ चुकी है।

वैश्विक कूटनीति के बदलते परिदृश्य के बीच इस दौरे में दोनों देशों ने संयुक्त 'जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029' की समीक्षा की और कई ठोस आउटकम्स/एम.ओ.यूज़ पर सहमति जताई। द्विपक्षीय व्यापार को 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। रक्षा उद्योग सहयोग, क्रिटिकल मिनरल्स, समुद्री परिवहन, कृषि, उच्च शिक्षा, नर्स भर्ती और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक समझौते हुए। सबसे महत्वपूर्ण, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को नई गति मिली। इटली भूमध्य सागर का अहम प्रवेश द्वार है, जिससे यह साझेदारी भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को 'एक्ट वेस्ट' की दिशा में भी मजबूत आधार देती है। जबकि विपक्ष 'मेलोडी' पर व्यंग्य कर रहा है, वास्तविकता यह है कि मोदी-मेलोनी ने दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की ठोस नींव रखी है।

यह यात्रा महज द्विपक्षीय नहीं, बल्कि बहुपक्षीय महत्व की है। दोनों नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की विविधता पर सहमति बनी। दोनों देशों ने एक्शन प्लान की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों के नेतृत्व वाले एक मैकेनिज़्म के गठन पर सहमति जताई है। यह संस्थागत मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मेलोनी की सरकार मजबूत राष्ट्रवादी रुख के साथ अवैध प्रवासन और यूरोपीय संप्रभुता पर सख्त नीति अपनाती है, जबकि मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' और मेलोनी की 'इटली फर्स्ट' सोच में स्पष्ट समानता दिखती है। दोनों ने साफ संदेश दिया कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की नींव पर खड़े देश एक-दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, वैश्विक संतुलन को नई दिशा दे सकते हैं। यह वह सोच है जिससे कांग्रेस और उसके गठबंधन वाले हमेशा कतराते रहे। वे तो अभी भी 'चीन भाई-चीन'

वाली पुरानी लीक पर अटके हैं।

इतिहास के पन्नों में यह यात्रा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव की एक सशक्त मिसाल के रूप में दर्ज हुई। कोलोसियम में संयुक्त भ्रमण, राजकीय रात्रिभोज, गार्ड ऑफ ऑनर और मेलोनी द्वारा हिंदी कहावत 'परिश्रम ही सफलता की कुंजी है' का उल्लेख–ये सभी क्षण दोनों देशों के बीच बढ़ती आत्मीयता को दर्शाते हैं। इटली में भारतीय समुदाय की उपस्थिति और सक्रियता लगातार मजबूत हो रही है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। भले ही कुछ लोग सांस्कृतिक कूटनीति को कम आँकते हों, पर वास्तविकता यह है कि सॉफ्ट पावर के बिना वैश्विक प्रभाव अधूरा रहता है, और इसी संतुलन को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है।

भारत और यूरोप के बीच आर्थिक रिश्ते अब नए विस्तार की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 16.77 बिलियन डॉलर के व्यापार आधार के साथ यह साझेदारी निवेश, तकनीक और संयुक्त उत्पादन को नई ऊर्जा दे रही है। रक्षा क्षेत्र में सह-उत्पादन के अवसर मजबूत हो रहे हैं, वहीं स्वच्छ ऊर्जा और एआई जैसे भविष्य-केंद्रित क्षेत्रों में सहयोग भारत को यूरोपीय तकनीकी क्षमता से और अधिक जोड़ रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को चीन से अलग करने की चल रही कोशिशों के बीच भारत की रणनीतिक भूमिका लगातार बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी नीति ने इस परिवर्तन में भारत को निर्णायक स्थिति में ला खड़ा किया है, जबकि विपक्ष अब भी बड़े आर्थिक दृष्टिकोण की बजाय सीमित मुद्दों तक ही सिमटा दिखाई देता है।

विपक्ष की आलोचना इस दौर की एक चिंताजनक सच्चाई बनकर सामने आती है। राहुल गांधी जैसे नेता जब 'टॉफी डिप्लोमेसी' पर व्यंग्य करते हैं, तो वे देश की गरिमा और विदेश नीति की गंभीरता को कमजोर करते प्रतीत होते हैं। जब भारत वैश्विक पटल पर मजबूती से अपनी स्थिति स्थापित कर रहा है, तब भी उन्हें विदेश नीति केवल 'मोदी का प्रचार' कहकर सीमित करने की प्रवृत्ति से आगे बढ़ते नहीं देखा जाता। यह भी स्मरणीय है कि वही विपक्ष पहले 'चीन के साथ दोस्ती' जैसे विचारों को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी इटली जैसे मजबूत यूरोपीय देश के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं, तब उनकी चुप्पी या तीखी आलोचना दोनों ही व्यापक राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में प्रश्न उठाती है।

मोदी-मेलोनी की यह 'मेलोडी' डिप्लोमेसी अब केवल एक कूटनीतिक संवाद नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति संरचना में भारत के निर्णायक उभार का स्पष्ट संकेत बन चुकी है। रोम की यह यात्रा दर्शाती है कि जब नेतृत्व सशक्त हो, दृष्टि स्पष्ट हो और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हों, तब परिणाम इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं।

यह वह समय है जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है और भारत उसमें दर्शक नहीं, सक्रिय निर्माता की भूमिका निभा रहा है। जो अब भी पुरानी राजनीतिक सोच और सीमित दृष्टि से इस परिवर्तन को आंकने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वाभाविक रूप से इस गति से पीछे रह जाएंगे। भारत आज रुकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए चल रहा है– आत्मविश्वास, सम्मान और वैश्विक प्रभाव के साथ।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। नोटः-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2009/34814 मो0 नं0 -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में मिला युवक का शव, हड़कंप

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के बछरावां रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास घोसियाना मोहल्ले में बृहस्पतिवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। युवक के पास खाली शराब और पानी की बोतलें पड़ी मिलीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक बुधवार शाम से झाड़ियों के पास बैठकर शराब पी रहा था। काफी देर तक वह वहीं दिखाई दिया था। बाद में युवक की पहचान नवरंग सिंह का पुरवा मजरे आलमपुर निवासी संदीप लोधी (22) पुत्र राम बहादुर के रूप में हुई। मृतक के भाई प्रदीप ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि संदीप नशे का आदी था। वह जम्मू में एक भट्ठे पर मजदूरी करता था और करीब 15 दिन पहले ही गांव लौटा था। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पंचायतनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत, उपजिलाधिकारी से दुकान हटवाने की मांग

महराजगंज, रायबरेली। तहसील क्षेत्र के ग्राम भदिहा मजरे मऊ निवासी माता फेर ने उपजिलाधिकारी महराजगंज को प्रार्थना पत्र देकर भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जे को हटवाने की मांग की है। प्रार्थी ने बताया कि ग्राम मऊ परगना सेमरौता स्थित गाटा संख्या 3575/0.1390 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में उसके नाम दर्ज है तथा वह वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जा करता चला आ रहा है। आरोप है कि विपक्षी राम सुमिरन व बाबूलाल निवासी देवी भक्त का पुरवा मजरे मऊ ने भूमि पर लोहे की गुमटी रखकर जबरन कब्जा कर लिया है। प्रार्थी का कहना है कि विपक्षी भविष्य में उसी स्थान पर पक्का निर्माण कराने की तैयारी में हैं, जिससे उसकी भूमि को नुकसान पहुंचा सकता है। मामले को लेकर प्रार्थी ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध कब्जा व दुकान हटवाने की मांग की है। उपजिलाधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम महराजगंज से शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि

लालगंज (रायबरेली)। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राजीव गांधी के योगदान को याद किया। कहा कि उन्होंने देश को आधुनिक सोच और नई तकनीक की दिशा दी। उनके कार्यों को देश हमेशा याद रखेगा। कांग्रेस सोशल मीडिया विंग की प्रदेश सचिव कमल सिंह चौहान ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के जनक थे। देश के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है।कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी के विचार और देशहित में किए गए कार्य आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष राजनारायण यादव, मन्नू लाल शुक्ला, न्याय पंचायत अध्यक्ष रुखसार अहमद, ग्राम सभा अध्यक्ष हरिश्चंद्र पासवान, राजबाबू, सुशील अग्निहोत्री, दुर्गेश, रामपाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

घरेलू कलह का खूनी अंत- पत्नी को बांके से काट डाला, फिर खुद फंदे पर झूला पति

● थानगांव के ईशरौली गांव में चीख-पुकार के बीच खूनी खेल, एक ही आंगन में मिले दो शव, मचा कोहराम

मां के सामने ही बहू पर वार करता रहा कलयुगी बेटा, जब तक गांव वाले दौड़े तब तक थम चुकी थीं सांसें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद- सीतापुर जनपद के थानगांव थाना क्षेत्र के ईशरौली गांव में घरेलू विवाद के चलते एक ऐसा खूनी खेल खेला गया, जिसने सुनने वालों की रूह कंपा दी। मामूली बात से शुरू हुई अनबन इस कदर हिंसक हो उठी कि एक सनकी पति ने अपनी ही जीवनसंगिनी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद पकड़े जाने के खौफ और आत्मग्लानि में आरोपी पति ने भी कमरे के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक ही घर से उठी दो लाशों के बाद पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक, ईशरौली गांव निवासी दीपक पुत्र गोबरे का अपनी पत्नी छाया के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि दीपक आपा खो बैठा। उसने घर में रखे धारदार हथियार बांके से छाया पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। कमरे से आ रही छाया की चीख-पुकार और शोर सुनकर दीपक की वृद्ध मां बदहवास होकर अंदर की तरफ दौड़ी। जैसे ही वह कमरे के मुहाने पर पहुंची, उसकी आंखों के सामने पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अपना बेटा अपनी बहू पर बेरहमी से वार कर रहा था। मां ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन दीपक के सिर पर खून सवार था। घबराई मां शोर मचाते हुए ग्रामीणों को बुलाने के लिए बाहर भागी। जब तक मां की गुहार सुनकर परिजन और ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर घर के भीतर दाखिल हुए, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आंगन में रखी चारपाई पर छाया का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था, जिससे दीपक की हैवानियत साफ बयां हो रही थी। वहीं, जब ग्रामीणों ने अंदर वाले कमरे का रुख किया, तो वहां का नजारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के बाद दीपक ने खुद भी छत के कुंडे से फंदा लटकाकर आत्महत्या कर ली थी। दोहरे संदेहास्पद और हिंसक मौत की सूचना मिलते ही थानगांव थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।

पुलिस ने खून से सने हथियार और अन्य साक्ष्यों को कब्जे में ले लिया है। दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, दीपक और छाया के बीच अक्सर छोटी-मोटी बातों को लेकर कहासुनी होती थी, लेकिन यह विवाद इस कदर खूनी रूप अख्तियार कर लेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था, जिसने दीपक को इतना बड़ा हैवान बना दिया। बहरहाल, इस दोहरी मौत के बाद से ईशरौली गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में अब एग्जाम कॉपियों के मूल्यांकन में होगी स्टेप मार्किंग, लाखों छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में पहली बार सभी विषयों में 'स्टेप मार्किंग' की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। इस निर्णय से विश्वविद्यालय के लाखों परीक्षार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब सब्जेक्टिव (विषयपरक/निबंधात्मक) प्रश्नपत्रों के उत्तरों को विभिन्न मुख्य बिंदुओं और चरणों में विभाजित कर जांचा जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी का अंतिम उत्तर किसी कारणवश त्रुटिपूर्ण भी होता है, लेकिन उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और शुरुआती चरण सही हैं, तो उसे प्रत्येक सही चरण के लिए निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। इस कदम से किसी भी विद्यार्थी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने द्वितीय परिसर में सभी विषयों के मूल्यांकन प्रभारियों के साथ बैठक में लिया। कुलपति ने कहा, अक्सर यह देखा जाता रहा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं की अधिक संख्या होने के कारण मूल्यांकन में एकरूपता की कमी रह जाती है, क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र को कई सारे परीक्षक जांचते हैं और सबका नंबर देने का तरीका अलग-अलग होता है जिससे विद्यार्थियों के अंकों में विसंगतियां आने की आशंका बनी रहती थी। इसलिए मूल्यांकन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। मूल्यांकन में पूर्ण एकरूपता बनाए रखने के लिए पहली बार मुख्य परीक्षक और उप-मुख्य परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक विषय में कितने मुख्य परीक्षक और डिप्टी हेड नियुक्त किए जाएंगे, इसका निर्धारण पूरी तरह से उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या के आधार पर किया जाएगा। किस विषय अथवा प्रश्नपत्र में कितने मुख्य परीक्षक नियुक्त होंगे, उनके नामों का चयन संबंधित विभागाध्यक्ष करेंगे। मूल्यांकन कार्य शुरू होने से पूर्व सभी मुख्य परीक्षक प्रत्येक प्रश्नपत्र सब्जेक्टिव का एक प्रामाणिक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के 'की वर्ड' निर्धारित किए जाएंगे, जिसके आधार पर ही सभी परीक्षक कापियों का मूल्यांकन करेंगे। कॉपियों की सुचारू जांच सुनिश्चित करने के लिए मुख्य परीक्षक प्रत्येक जांचे गए बंडल में से अनिवार्य रूप से कुल उत्तर पुस्तिकाओं के न्यूनतम पांच प्रतिशत कापियों की स्वयं रैंडम जांच करेंगे। पूर्व में उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल 25 कॉपियों के बनाए जाते थे, जिन्हें अब बढ़ाकर प्रति बंडल 50 कापी कर दिया गया है। उत्तर पुस्तिकाएं अब परीक्षा केंद्रों से सीधे अधिकृत केंद्रीय एजेंसी को भेजी जाएंगी, जहां से उन्हें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों को आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षक के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 50 कापियां जांचना अनिवार्य घोषित किया गया है। मूल्यांकन केंद्रों का समय सुबह छह बजे से ही शुरू हो जाएगा।

मदरसा उस्मानिया जियाउल उलूम में शानदार सम्मान समारोह, मेधावी छात्र-छात्राएं हुए सम्मानित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

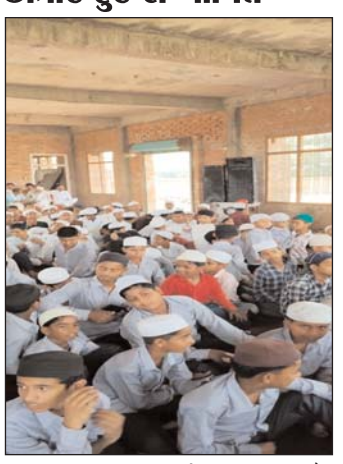

महमूदाबाद- सीतापुर महमूदाबाद के वार्ड शेरापुर स्थित मदरसा उस्मानिया जियाउल उलूम में मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हाईस्कूल टॉपर सहित विभिन्न कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पत्रकार अनुज कुमार जैन रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में आमिर अरफ़ात तथा सोशल मीडिया क्रिएटर एवं अभिनेता डिल्लन वारसी मौजूद रहे। अतिथियों ने मेधावी बच्चों को शील्ड प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान मदरसा के प्रधानाचार्य मोहम्मद इमरान ने सभी मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में हाईस्कूल टॉपर निदा, मोहम्मद आमीन, शगुफ्ता, परवीन बानो, अक्सा सहित अन्य छात्र-छात्राएं शामिल रहीं। मुख्य अतिथि अनुज कुमार जैन ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही समाज और देश के विकास का सबसे मजबूत आधार है। बच्चों की मेहनत और शिक्षकों का समर्पण ही उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। ऐसे सम्मान समारोह विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में तेजनीपुर इंटर कॉलेज के प्रबंधक कमलेंद्र वर्मा, भगौती प्रसाद इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुनील वर्मा, मदरसा के प्रधानाचार्य हाफिज गुलाम वारिस, मौलाना उस्मान कासमी, मौलाना रमजान, मोहम्मद ईशहाक, हाफिज इकराम, हाफिज मैनुद्दीन, मास्टर तालिब, मो इसरार, जय प्रकाश वर्मा, प्रदीप वर्मा, शुभम वर्मा, सना खातून, शहाना शेख, गौसिया, शहाना खातून, सबा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वी पुण्य तिथि पर कांग्रेस जनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

बिसवां- सीतापुर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 35वीं पुण्य तिथि पर कांग्रेस जनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमर मेहरोत्रा ने स्वर्गीय गांधी को संचार क्रांति का जनक व आधुनिक भारत का शिल्पकार तथा पंचायती राज के प्रणेता बताया। वही प्रदेश कांग्रेस आर टी आई के महासचिव रजनीश कुमार मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार कंप्यूटर क्रांति पंचायती राज व्यवस्था नवोदय विद्यालय व 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे न जाने कितनी व्यवस्थाएं उन्होंने देश की जनता को दिया ।जो आज की जनता इसका लाभ उठा रही है। साथ ही देश विकास की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर रमेश चंद्र गौड़करीम अंसारी अरुण श्रीवास्तव मुजीब खान महेंद्र त्रिपाठी इसराइल बानो अवधेश रावत मोनू तिवारी दिलीप वर्मा सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे।

श्रद्धा और सेवा का संगम : पूरे चंदू में विशाल ब्रह्मभोज,हजारों लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद

● पूर्वजों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में उमड़ी भीड़,दूरदराज से पहुंचे लोग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज(रायबरेली)। विकास खंड सरेनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत काल्हीगांव स्थित पूरे चंदू गांव में गुरुवार को आयोजित विशाल ब्रह्मभोज में श्रद्धा,सेवा और सामाजिक समरसता का अनूठा दृश्य देखने को मिला।आयोजन में क्षेत्र सहित दूर-दराज के गांवों से पहुंचे हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया।उल्लेखनीय है कि यह ब्रह्मभोज स्वर्गीय पूर्वजों की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया था।ब्रह्मभोज में ग्रामीणों के साथ-साथ कुटुंबों को भी सम्मानपूर्वक भोजन कराया गया,जिसकी क्षेत्र में सराहना हो रही है।पूरा गांव धार्मिक माहौल में डूबा नजर आया।सुबह से ही श्रद्धालुओं और मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था,जो देर शाम तक जारी रहा। आयोजन स्थल पर भोजन,पेयजल और बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी।व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव के युवाओं और परिजनों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।आयोजनकर्ता शिवप्रसाद त्रिवेदी (मनऊ त्रिवेदी) ने बताया कि यह आयोजन पूर्वजों के आशीर्वाद और उनकी स्मृति को समर्पित है। उन्होंने कहा कि समाज और परिवार के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।साथ ही साथ कहा कि ब्रह्मभोज केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं,बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम भी है।उन्होंने कहा कि पूर्वजों की स्मृति और उनके आशीर्वाद से ही इस तरह के आयोजन संपन्न होते हैं।

समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई।उन्होंने कहा,हमारा प्रयास रहा कि यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक प्रसाद ग्रहण करे।लोगों का स्नेह और सहयोग ही इस आयोजन की सबसे बड़ी पूंजी है।कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोगों,ग्रामीणों और रिश्तेदारों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही।पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बना रहा।

पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस और प्रशासन के फूले हाथ-पॉव!

● 'इंसाफ की जंग... या प्रशासन को खुली चुनौती? महमूदाबाद में एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर वो हंगामा काटा कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया!'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद- सीतापुर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपनी मांगों और कथित उत्पीड़न के खिलाफ पानी की टंकी पर जा चढ़ा। युवक के टंकी पर चढ़ते ही वहां तमाशबीनों का हुजूम उमड़ पड़ा और आनन-फानन में स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अधिकारियों की सूझबूझ और काफी समझाने-बुझाने करीब 2 मिनट की सीधी बातचीत और अथक प्रयास के बाद युवक को सकुशल नीचे उतारा जा सका। टंकी से नीचे उतरने के बाद पीड़ित युवक मेराज ने मीडिया के सामने रोते हुए अपना दर्द बयां किया। युवक ने गांव के ही एक दबंग अब्दुल रज्जाक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि उसका परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से ग्राम सहरी, महमूदाबाद स्थित जमीन पर रह रहा है। साल 2007 में विपक्षियों ने उसके पिता और परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसके दो महीने बाद उसके पिता का निधन हो गया। आरोप है कि विपक्षी ने उनके घर के सामने जबरन जानवर बांध रखे थे। जब प्रशासन के लेखपाल और पुलिस ने शिकायत पर जानवर हटवाए, तो दबंगों ने रंजिश में उनके घर पर हमला कर दिया। युवक की उंगली पर चोट आई, उनकी गर्भवती भैंस खोल ली गई, हैंडपंप उखाड़ दिया गया और शौचालय तक तोड़ डाला गया। मेराज का आरोप है कि इतनी ज्यादती के बाद भी पुलिस ने उल्टा उनके ही परिवार के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि दूसरे पक्ष के सिर्फ 2 लोगों पर कार्रवाई हुई। पीड़ित युवक का बयान है कि मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है। हमारे पास मुकदमा लड़ने के पैसे नहीं हैं। मैं पढ़ूं-लिखूं या हर हफ्ते कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटूं? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे ऊपर किया गया झूठा मुकदमा वापस लिया जाए और हमें इंसाफ मिले। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और डॉ. अम्मार रिजवी ने युवक से लगातार बातचीत की और उसे हर संभव कानूनी मदद और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। तब कहीं जाकर युवक का गुस्सा शांत हुआ और उसने नीचे आने का फैसला किया। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन इस घटना ने स्थानीय स्तर पर पुलिसिया कार्रवाई और गरीबों की सुनवाई पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या महमूदाबाद पुलिस इस 17 साल के बेबस युवक को इंसाफ दिला पाएगी?

69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार फिर बनाएगी चयन सूची

● परिषदीय विद्यालयों की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार अब हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर नई चयन सूची तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को छह सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है, जिससे पात्र अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब बेसिक शिक्षा परिषद दोबारा चयन सूची तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के आधार पर नई चयन सूची बनाई जाएगी। इस सूची में जो अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे, उन्हें नियुक्ति देने पर सरकार विचार करने को तैयार है। बेसिक शिक्षा परिषद अब आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गया है। यह भर्ती वर्ष 2020 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार यह फैसला मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ले रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि इस आदेश को भविष्य के मामलों में उदाहरण के रूप में नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नियुक्ति केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिनका नाम संशोधित चयन सूची में आएगा, जिनके लिए रिक्त पद उपलब्ध होंगे और जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करेंगे। अदालत ने पूरी प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को नियमित पीठ के समक्ष होगी। इस आदेश के बाद उन अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो संशोधित चयन सूची में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं।

मदरसा अजमतुल उलूम में परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन

बिसवां, सीतापुर। नगर के मोहल्ला शेखसराय स्थित मदरसा अजमतुल उलूम में परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जामा मस्जिद के सेक्रेट्री हाफिज मोहम्मद अय्यूब खां तथा नायब सदर मोहम्मद अय्यूब खान उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों ने बच्चों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की प्रेरणा देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने अभिभावकों से भी अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने और उन्हें आगे तक पढ़ाने का आग्रह किया। इस अवसर पर मदरसे में अपनी-अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कक्षा एक से मोहम्मद अमान, कक्षा दो से साहिबा, कक्षा तीन से मोहम्मद आसम, कक्षा चार से कुलसूम तथा कक्षा पांच से सबा शामिल रहीं। कार्यक्रम में मदरसे के शिक्षक, अभिभावक एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे।

11 वर्षीय मासूम की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद, मारकर गन्ने के खेत में फेंका था शव

● पबरेली कोर्ट ने 2019 में 11 वर्षीय गुलाब सिंह की हत्या के मामले में किशन श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बच्चे का अपहरण कर गला घोंटकर हत्या की गई थी और शव गन्ने के खेत में मिला था।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बरेली। सात साल पुराने 11 साल के बच्चे की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने हत्या के दोनों आरोपितों किशन श्रीवास्तव उर्फ कृष्णा और हिमांशु शर्मा को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह दर्दनाक मामला इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अहलादपुर गांव का है। नौ अप्रैल 2019 की शाम करीब साढ़े सात बजे 11 साल का मासूम गुलाब सिंह अपने घर से अचानक लापता हो गया था। बच्चे के स्वजन ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन जब उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला, तो गुमशुदगी दर्ज कराई। 12 अप्रैल की सुबह गांव के ही एक गन्ने के खेत में बच्चे का सड़ा-गला शव बरामद हुआ। मामले की जांच में साफ हुआ कि गांव के ही रहने वाले किशन श्रीवास्तव उर्फ कृष्णा और हिमांशु शर्मा ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) अभय श्रीवास्तव की कोर्ट में यह तथ्य प्रमुखता से आया कि घटना वाली शाम एक चश्मदीद ने मासूम गुलाब सिंह को आखिरी बार दोनों दोषियों के साथ गन्ने के खेत की दिशा में जाते हुए देखा था। इसके अलावा, वारदात के बाद दोनों आरोपितों का गांव से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना, बच्चे की तलाश में परिवार की कोई मदद न करना और उनका संदिग्ध व्यवहार उनके विरुद्ध सबसे मजबूत साक्ष्य बना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी क्रूरता की पुष्टि की, जिसमें साफ हुआ कि मासूम की हत्या गला घोंटकर की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक स्वतंत्र पाठक ने कोर्ट में नौ गवाह पेश किए। अपराध की गंभीरता और क्रूरता को देखते हुए न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की कड़ी सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने में से एक लाख रुपये की राशि पीड़ित पिता इंद्रपाल को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अपहरण और साक्ष्य मिटाने के जुर्म में भी उन्हें क्रमशः तीन और सात साल के कठोर कारावास तथा अतिरिक्त जुर्माने की सजा दी गई है।

बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक संपन्न

● आपसी सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद- सीतापुर आगामी बकरीद (ईद-उल-अजहा) के त्योहार को क्षेत्र में सकुशल, शांतिपूर्ण और गरिमामय ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से स्थानीय कोतवाली परिसर में एक महत्वपूर्ण पीस कमेटी (शांति समिति) की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं, संभ्रांत नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और त्योहार को आपसी भाईचारे, कौमी एकता तथा पारंपरिक सौहार्द के साथ मनाने का साझा संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहीं उपजिलाधिकारी ने क्षेत्रीय पुलिस क्षेत्राधिकारी और कोतवाली प्रभारी की मौजूदगी में कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि त्योहार के दौरान क्षेत्र की गंगा-जमुनी तहजीब को हर हाल में कायम रखा जाएगा। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर ध्यान न देने तथा इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। बैठक के दौरान नगर और ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी समस्याओं तथा त्योहार के मद्देनजर व्यापक चर्चा की गई। मौलाना नूरुल हुदा, मौलाना रईस और मौलाना उस्मान ने संयुक्त रूप से कहा कि इस्लाम शांति और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने अपील की कि कुर्बानी खुले स्थानों पर न की जाए और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे किसी भी सह-नागरिक को असुविधा न हो। प्रबुद्ध नागरिक चक्रसुदर्शन पांडे ने कहा कि महमूदाबाद का इतिहास हमेशा से आपसी मेल-मिलाप का रहा है और इस बार भी सभी समुदाय मिलकर इस पर्व की खुशियों को साझा करेंगे। नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि राम नरेश ने आश्वस्त किया कि बकरीद के मद्देनजर नगर में साफ-सफाई, चूने के छिड़काव और सुचारू जलापूर्ति के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रधान संघ के पदाधिकारियों ने ग्रामीण अंचलों में भी शांति समितियां बनाकर प्रशासनिक दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन कराने की बात कही। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिक जिम्मेदार बनें, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें और त्योहार की पवित्रता तथा शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।बैठक के समापन पर कोतवाली प्रभारी ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और शरारती तत्वों पर ड्रोन व खुफिया तंत्र के जरिए कड़ी नजर रखी जाएगी। इस अवसर पर भारी संख्या में क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, व्यापार मंडल के पदाधिकारी और प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

बुजुर्ग को गिरफ्तार क्यों किया... लिखकर दें'; बॉम्बे HC ने सरकार पर ठोका जुर्माना

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ी अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि, वह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक 70 साल के याचिकाकर्ता की निजी आजादी के हनन के लिए उसे 25,000 रुपये का मुआवजा दे। दरअसल, एक बुजुर्ग याचिकाकर्ता, जो कि एक कारोबारी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। यह मामला उनकी बहू ने दर्ज कराया था, जिसने उन पर अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाने और अन्य अपराधों का आरोप लगाया था। उन्होंने दलील दी कि पुलिस ने अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया और पुलिस नोटिस का जवाब देने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई करते हुए, नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी फालके और जस्टिस निवेदिता मेहता ने पाया कि नोटिस में गिरफ्तारी की वजह का कहीं भी जिक्र नहीं था। कोर्ट ने यह भी पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी मेमोरेंडम भी नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी अपने आप नहीं हो जाती, बल्कि इसके लिए तय मानदंडों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। बेंच ने आगे कहा, पुलिस किसी भी आरोपी को तब तक हिरासत में नहीं ले सकती, जब तक उसे गिरफ्तारी की वजह लिखित में न बता दी जाए। इसके अलावा कानून लागू करने वाली एजेंसियों की भूमिका पर कड़ी टिप्पणियां करते हुए कहा, 'जब कोई पुलिस अधिकारी ही कानून का उल्लंघन करता है, तो ऐसे उल्लंघन के लिए सजा भी उसी अनुपात में कड़ी होनी चाहिए, ताकि यह एक प्रभावी रोक का काम कर सके। '

राघव चड्ढा की तस्वीर और आवाज के दुरुपयोग पर रोक की याचिका खारिज, दिल्ली HC ने कहा- राजनीतिक व्यंग्य पर रोक नहीं

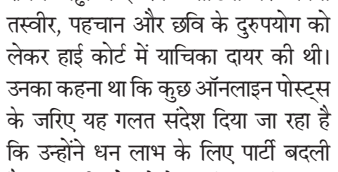

दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा की आवाज और तस्वीर के दुरुपयोग को रोकने की मांग याचिका पर अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि राजनीतिक आलोचना, व्यंग्य और कार्टून पर केवल इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वे किसी नेता को अप्रिय लगते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आलोचना और मानहानि के बीच बहुत पतली रेखा होती है व लोकतंत्र में व्यंग्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन का मामला नहीं बनता, क्योंकि जिन पोस्ट्स पर आपत्ति जताई गई है वे राजनीतिक फैसलों की आलोचना से संबंधित हैं। अदालत ने मशहूर कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण के राजनीतिक कार्टूनों का भी उल्लेख किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि चड्ढा को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान होने का दावा है तो वे मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता को मानहानि से जुड़ी मांग जोड़ने के लिए संशोधन की अनुमति दे दी। राघव चड्ढा ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी तस्वीर, पहचान और छवि के दुरुपयोग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि कुछ ऑनलाइन पोस्ट्स के जरिए यह गलत संदेश दिया जा रहा है कि उन्होंने धन लाभ के लिए पार्टी बदली है। चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने दलील दी कि इंटरनेट मीडिया सामग्री उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। वहीं मेटा की ओर से कहा गया कि जिन पोस्ट्स का हवाला दिया गया है उनमें कई समाचार रिपोर्ट्स या सामान्य सामग्री हैं।

'मिट जाओगे', अमेरिका की धरती से पाकिस्तानी सांसद ने भारत के खिलाफ उगला जहर

● अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी सांसद राणा महमूद-उल-हसन ने भारत और जम्मू-कश्मीर पर भड़काऊ बयान दिए, जिसमें भारत को धमकी भी शामिल थी। इन बयानों पर सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ और ऐसे नेताओं के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली। अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के एक सांसद के भारत विरोधी बयान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेता और सीनेटर राणा महमूद-उल-हसन ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत और जम्मू-कश्मीर को लेकर कई भड़काऊ बयान दिए। अमेरिका की राजनीतिक टिप्पणीकार और पत्रकार एमी मेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्यक्रम को लेकर लंबी पोस्ट साझा की। उन्होंने इस कार्यक्रम को 'अमेरिकी धरती से भारत को दी गई सीधी धमकी' बताया। एमी मेक के मुताबिक, राणा महमूद-उल-हसन ने करीब एक घंटे के भाषण में भारत के खिलाफ तीखे बयान दिए और 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई की तारीफ की।

भारत को दी धमकी

अपने भाषण में राणा महमूद-उल-हसन ने कहा, 'ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों... तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में।' उन्होंने पाकिस्तानियों से भारत के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की बात भी कही। उन्होंने कहा, 'जब कुछ न बन सका तो डुबो देंगे सफीना... हम लड़ेंगे आखिरी दम तक अपने मुल्क के दिफा के लिए। 'पाकिस्तानी सीनेटर ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान हर मोर्चे पर लड़ाई जारी रखेगा।

सोशल मीडिया पर भारी विरोध

राणा महमूद-उल-हसन के भाषण का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखने को मिली। एमी मेक ने मांग की कि ऐसे पाकिस्तानी नेताओं के भविष्य में अमेरिका आने पर रोक लगाई जाए, जो वहां जाकर नफरत फैलाते हैं। उन्होंने लिखा कि यह एक ऐसे देश के वरिष्ठ नेता का बयान है, जिस पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, और वह अमेरिका की धरती पर भारत जैसे लोकतांत्रिक सहयोगी देश के खिलाफ खुलेआम धमकी दे रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बयान की आलोचना की। कुछ यूजर्स ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों की ज्यादा जांच की मांग की, जबकि कई लोगों ने इस भाषण को भड़काऊ और गैर-जिम्मेदाराना बताया।

महिलाओं के लिए डीयू में बिना नियमित कॉलेज पीजी करने का सुनहरा अवसर

दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नॉन-कॉलेजिएट वुमंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में दिल्ली की उन छात्राओं के लिए यह बड़ा अवसर है, जो नियमित कॉलेज जाए बिना डीयू से मास्टर डिग्री हासिल करना चाहती हैं। विश्वविद्यालय ने छात्राओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। एनसीडब्ल्यूईबी के तहत एमए और एमएससी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक छात्राएं 7 जून 2026 रात 11:59 बजे तक डीयू के पीजी प्रवेश पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार केवल दिल्ली में रहने वाली छात्राएं ही इस बोर्ड के तहत आवेदन करने की पात्र होंगी। एनसीडब्ल्यूईबी के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, अरबी और फारसी सहित कई विषयों में एमए की सुविधा उपलब्ध है। वहीं गणित विषय में एमए और एमएससी दोनों पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। अधिकतर पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के लिए श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के तहत 29-29 सीटें निर्धारित की गई हैं। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार सीटों का लाभ मिलेगा। प्रवेश सीयूईटी-पीजी 2026 के अंकों और सीएसएएस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। एससी, एसटी और दिव्यांग छात्राओं के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये, जबकि सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 250 रुपये तय किया गया है।

'मोटी' कहने पर भड़कीं सारा तेंदुलकर, सचिन की बेटी ने लगा दी पैपराजी की क्लास

● पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर का नाम इस वक्त एक वायरल पोस्ट को लेकर चर्चा में बना हुआ है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर बी टाउन में भी काफी चर्चा में रहती हैं। अपने हॉट लुक्स को लेकर वह लाइमलाइट में छाई रहती हैं। लेकिन इस वक्त वजह कुछ और है, जिसके चलते सचिन की बेटी का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर एक पैपराजी पेज द्वारा सारा तेंदुलकर का वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें सारा की बॉडी शेमिंग की गई है। इसको लेकर अब उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है और उस पैपराजी को लताड़ लगाई है। सारा तेंदुलकर बेशक कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं हैं। लेकिन अपनी बेबाक खूबसूरती के दम पर वह हिंदी सिनेमा की कई हसीनाओं पर भारी पड़ती हैं। इतना ही नहीं आए दिन सारा तेंदुलकर ने अलग-अलग जहग पर स्पॉट होती हैं, जिसकी वजह से पैपराजी के कैमरों में उनकी झलक कैद होती रहती है। हाल ही में एक पैपराजी पेज ने सारा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया है और उनका रील वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें लिखा है- मोटी वाली सारा है और बगल वाली भाभी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सारा तेंदुलकर की बॉडी शेमिंग का मामला चर्चा में आ गया है। सारा ने इस मामले पर गुस्सा जाहिर करते हुए पैपराजी के पोस्ट को अपने इंस्टा स्टोरी में शेयर किया है और लिखा है तुम घिनौने हो, ये कोई पत्रकारिता नहीं, हमें अकेला छोड़ दो। तुम बेशक अपनी पोस्ट डिलीट कर सकते हो, लेकिन इससे तुम कम घिनौने नहीं हो जाओगे। इस तरह से सारा तेंदुलकर ने पैपराजी की जमकर क्लास लगाई है। ये पहला मौका नहीं है, जब सोशल मीडिया पर सारा को बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा है, इससे पहले भी कई बार उनके साथ ये हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये है कि वह अपने आलोचकों को मुहंतोड़ जवाब देना अच्छे से जानती हैं।

शिलचर-आसाम विश्वविद्यालय मार्ग की हालत बदहाल

● छात्रों व स्थानीय लोगों में आक्रोश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास के मध्य नजर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है लेकिन असम के शिलचर से असम विश्वविद्यालय जाने वाली शिलकुड़ी क्षेत्र की सड़क की जर्जर हालत ने आम लोगों, छात्रों और शिक्षकों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही को बेहद कठिन बना दिया है। शिलकुड़ी डाकघर से लेकर कैंप क्षेत्र तक सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के कारण दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, लंबे समय से इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे गड्ढे और भी गहरे हो गए हैं। बारिश के चलते इनमें पानी भर जाने से स्थिति और खराब हो गई है। हर दिन हजारों छात्र-छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी और आम नागरिक इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। ऑटो, बाइक और कार चालकों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर छोटे-मोटे हादसे भी हो चुके हैं। बरसात के दौरान कीचड़ और जलभराव के कारण जाम की स्थिति भी आम हो गई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि यह मार्ग असम विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा है, जहाँ प्रतिदिन राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे में सड़क की यह स्थिति प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। इस मुद्दे पर नागरिकों और छात्रों ने तत्काल मरम्मत कार्य की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इस समस्या के समाधान के लिए हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।

एक्सीडेंट में घायल 8 साल के बच्चे को मुआवजे से इनकार

दिल्ली। सुंदर नगरी में सड़क हादसे में घायल आठ साल के बच्चे को मुआवजा देने से इनकार करते हुए कड़कड़डूमा अदालत ने कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि केवल चार्जशीट के आधार पर जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। अदालत ने साफ कहा कि दावों को साबित करने के लिए विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं करने पर हर मामले में बिना जांच के मुआवजा देना पड़ेगा। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूरल ने 2023 के एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया। पीठासीन अधिकारी विजय कुमार झा ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि बच्चे को गंभीर चोटें लापरवाह और तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण लगी थीं। मामला सुंदर नगरी का है, जहां मार्च 2023 में आठ वर्षीय आतिफ अपने पिता के साथ सड़क पार कर रहा था। आरोप था कि एक मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मारी। इस मामले में नंद नगरी थाने में केस दर्ज कर चार्जशीट भी दायर की गई थी। ट्रिब्यूनल को साक्ष्यों और गवाहियों में कई विरोधाभास मिले। अस्पताल के रिकॉर्ड में यह नहीं पाया गया कि बच्चे के पिता उसे अस्पताल लेकर गए थे। अदालत ने कहा कि यदि केवल चार्जशीट के आधार पर मुआवजा दिया जाए, तो न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।

इबोला के बढ़ते खतरे के बीच टला भारत-अफ्रीका शिखर सम्मलेन, दिल्ली में होना था कार्यक्रम

● इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत और अफ्रीकी संघ के बीच 28 मई 2026 को नई दिल्ली में होने वाला शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में इबोला वायरस से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत और अफ्रीकी संघ के बीच होने वाले शिखर सम्मलेन को रद कर दिया गया। यह आयोजन 28 मई 2026 को नई दिल्ली में होना था। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी। सरकार के अनुसार, अफ्रीका के कई हिस्सों में घातक इबोला वायरस के मामले सामने आए हैं। हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) के साउथ किवु प्रांत में नए मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन को बाद की तारीख पर करने का निर्णय लिया। नई तिथियां आपसी विचार-विमर्श के बाद तय की जाएंगी।

भारत-अफ्रीकी शिखर सम्मेलन टला

भारत और अफ्रीकी संघ की अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच हुई चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने, अफ्रीका छष्ठष्ट और संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों को समर्थन देने पर सहयोग जारी रखने का महत्व दोहराया।

भारत में इबोला का एक भी मामला नहीं

भारत में अभी तक इबोला का कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। फिर भी केंद्र सरकार ने पूरे देश में निगरानी और तैयारियों को बढ़ा दिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हवाई अड्डों पर प्री-अराइवल और पोस्ट-अराइवल स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन प्रोटोकॉल, केस मैनेजमेंट, रेफरल मैकेनिज्म और लैब टेस्टिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) सुनिश्चित करें।

इबोला वायरस कितना खतरनाक?

इबोला वायरस की कई स्ट्रेन हैं। वर्तमान प्रकोप बुंडीबुग्यो वैरिएंट से जुड़ा है, जो जायर वैरिएंट जितना घातक नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना जरूरी है। 2014-2016 के पश्चिम अफ्रीका महामारी की याद अभी भी ताजा है।यह स्थगन स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने का उदाहरण है। भारत और अफ्रीका के बीच मजबूत साझेदारी भविष्य में और गहरी होगी। सम्मेलन की नई तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

रोहित शर्मा का World Cup 2027 से कटेगा पता! हिटमैन के रवैये से नाराज है टीम मैनेजमेंट

● रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। रोहित का वर्ल्ड कप 2027 में खेलना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। उनसे टीम मैनेजमेंट भी नाराज है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली। भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर बड़ी समस्या सामने आ रही है। उनकी फिटनेस की वजह से वर्ल्ड कप 2027 में खेलना भी सवालों के घेरे में है। रोहित आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में चोटिल हुए थे और कुछ मुकाबले में नहीं खेल सके थे। इसके बाद वे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं, जिससे उनकी फिटनेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहित को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में जगह मिली है। उन्हें भारतीय टीम में चुना गया है लेकिन उनका खेलना पक्का नहीं है क्योंकि उन्हें पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। उनके लगातार चोटिल होने की वजह से वर्ल्ड कप 2027 में खेलने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी शर्मा की फिटनेस को लेकर चिंतित है।

रोहित शर्मा की फिटने से BCCI चिंतित

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, रोहित उन तीन हफ्तों के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलें में नहीं आए। उनका शरीर पहले से पतला हुआ है लेकिन इस बात को लेकर चिंता है कि क्या वे 50 ओवर तक फील्डिंग कर सकते हैं। उन्हें 50 ओवर फील्डिंग करनी होगी क्योंकि आईपीएल की तरह यहां पर इम्पैक्ट प्लेयर का नियम नहीं होता है। जब आप 40 के करीब होते हैं, तो शरीर ठीक होने में समय लगता है।

यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं बैकअप ओपनर

रोहित अगर पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं, तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में ईशान किशन को इस वजह से

चुना गया है ताकि वे सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभा सकें। हालांकि, अगर रोहित के विश्व कप में खेलने पर संशय हुआ, तो जायसवाल उनकी जगह पारी की शुरुआत कर सकते हैं। उन्हें बैकअप ओपनर के तौर पर चयनकर्ताओं ने तैयार करना शुरू भी कर दिया है।

रोहित से खुश नहीं टीम मैनेजमेंट

रिपोर्ट में बताया गया है कि रोहित से टीम मैनेजमेंट खुश नहीं है। रोहित ने 2023 विश्व कप में आक्रामक अंदाज में शुरुआत की थी। वे पहली ही गेंद पर अटैक करने को देखते हैं। हालांकि, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्होंने, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बैटिंग की, तो उनकी बल्लेबाजी में वो आक्रामक रुख नहीं दिखा। उनके आक्रामक शैली नहीं अपनाने की वजह से मैनेजमेंट नाराज है।

बराक घाटी में बिजली दुर्घटना पीड़ितों के लिए समान मुआवज़े की मांग

● मुन्नी छेत्री ने मनोतोष दास के परिवार को 20 लाख रुपये सहायता देने की सरकार से गुहार लगायी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: बराक घाटी में बिजली दुर्घटना पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता देने में कथित भेदभाव को लेकर समाज सेविका मुन्नी छेत्री ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि सभी पीड़ित परिवारों को समान रूप से सहायता प्रदान की जाए। मुन्नी छेत्री ने कहा कि यदि अल्गापुर काठलिछड़ा निवासी राजिबुल हक़ को परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया गया है, तो उत्तर करीमगंज विधानसभा के निवासी मनोतोष दास के परिवार को भी समान रूप से 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी सहायता में किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। मनोतोष दास का परिवार बेहद असहाय स्थिति में है और उन्हें न्यायपूर्ण सहायता मिलना जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करने की अपील की। मुन्नी छेत्री ने यह भी कहा कि मानवीय आधार पर सरकार को बिजली दुर्घटना के सभी पीड़ित परिवारों के लिए एक समान मुआवज़ा नीति लागू करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असमानता की शिकायत न उठे। स्थानीय लोगों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द सकारात्मक कदम उठाने की अपील की है।

दिल्ली के मंडावली में महिला की संदिग्ध हालत में मौत, एक साल पहले हुई थी शादी

दिल्ली। मंडावली इलाके में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हो गई। मृतक की पहचान गीता ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिछले साल ही महिला की शादी हुई थी। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 9:50 बजे पुलिस को एक पीसीआर काल मिली थी की एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मौके के निरीक्षण के दौरान क्राइम टीम ने महिला के शव पर गले में फंदे के निशान पाए। घटनास्थल से एक दुपट्टा बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल भेज दिया। महिला के पति राकेश कुमार से पुलिस पूछताछ कर रही है।

बांद्रा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर भारी पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन के समीप बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा शुरू की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दूसरे दिन बुधवार को दोपहर तीन बजे के बाद अचानक माहौल बिगड़ गया। बस्ती के कुछ स्थानीय युवकों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिस और नगर निगम के दस्ते पर अचानक पथराव शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें थीं। इस मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने बीएमसी को तत्काल प्रभाव से अवैध निर्माणों को ढहाने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बीएमसी की टीम मंगलवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी। पहले दिन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई थी, लेकिन बुधवार दोपहर को जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़े, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे के बाद अचानक भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते पथराव इतना तेज हो गया कि पुलिस और बीएमसी कर्मचारियों को खुद को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। उपद्रवियों ने सरकारी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बांद्रा स्टेशन के

बाहर यात्रियों में डर का माहौल पैदा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त पुलिस बल और दंगा नियंत्रण पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को खदेड़ा। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन के अनुसार, उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

दिल्ली में बिजली की मांग ने बनाया नया रिकॉर्ड

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से तापमान बढ़ने के साथ ही लू की स्थिति बनी हुई है। इससे बिजली की खपत बढ़ गई है। मई माह में ही मांग आठ हजार मेगावाट से ऊपर पहुंच गई है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार मांग अधिक है। अधिकतम मांग के साथ ही न्यूनतम मांग में भी वृद्धि देखी जा रही है। इससे पहले मई में बिजली की मांग आठ हजार मेगावाट से अधिक वर्ष 2024 में पहुंची थी। उस वर्ष भी 29, 30 व 31 मई को मांग आठ हजार मेगावाट से अधिक पहुंची थी। इस बार 20 मई को ही मांग आठ हजार से ऊपर दर्ज की गई है। वहीं, न्यूनतम मांग भी पांच हजार मेगावाट से ऊपर पहुंच गई है। मई के शुरू में न्यूनतम मांग चार हजार मेगावाट के आसपास रहती थी। पिछले सप्ताह यह लगभग 45 सौ मेगावाट के आसपास थी। बुधवार को यह 5174 मेगावाट दर्ज हुई थी। बृहस्पतिवार को यह बढ़कर 5211 मेगावाट पहुंच गई।

नीट पेपर लीक- CBI हिरासत में स्टूडेंट का पिता; बेटे के लिए लीक प्रश्नपत्र हासिल करने का आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पुणे- देशभर में सनसनी मचा देने वाले पुणे 7 देशभर में सनसनी मचा देने वाले NEET परीक्षा पेपर लीक मामले में अब चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। पहले पेपर लीक करने और बेचने वाले रैकेट से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब सीधे एक छात्र के पिता को ही CBI ने हिरासत में लिया है। लातूर के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे को पुणे से देर रात CBI द्वारा हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आने से चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। CBI की प्रारंभिक जांच के अनुसार, NEET-UG 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में एक बड़ा रैकेट सक्रिय था। जांच में सामने आया है कि इस रैकेट के तार पुणे, लातूर और राजस्थान तक जुड़े हुए थे। करीब 150 सवाल उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख रुपये का सौदा होने की जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। इस पूरे मामले में कुछ कोचिंग क्लासेस, बिचौलियों और परीक्षा से जुड़े लोगों की भूमिका होने का शक जताया जा रहा है। जांच के दौरान CBI ने पहले पुणे के एक केमिस्ट्री प्रोफेसर को इस रैकेट का 'किंगपिन' बताते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद लातूर की RCC कोचिंग संस्था से जुड़े आरोपियों पर भी कार्रवाई की गई। इसी जांच के दौरान डॉ. मनोज शिरुरे का नाम सामने आने की बात कही जा रही है। आरोप है कि अपने बेटे को परीक्षा में फायदा दिलाने के लिए उन्होंने लीक प्रश्नपत्र हासिल किए थे। CBI की टीम ने पुणे में डॉ. शिरुरे से कई घंटों तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इस मामले में आर्थिक लेन-देन, फोन कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल चैट्स और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई बातचीत की भी जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इस बीच, NEET पेपर लीक मामले को लेकर देशभर के लाखों छात्रों में भ्रम और नाराजगी का माहौल है। परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं और जांच एजेंसियों का मानना है कि इस रैकेट में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।